

दैनिक जागरण पृष्ठ 15  
9-9-2016

# किसान को दलहन के मिलेंगे वाजिब दाम

► नाफेड, एसएफएसी व एफसीआई को दिए गए सीधी खरीद के निर्देश

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

सरकार ने बृहस्पतिवार को नाफेड सहित खरीद एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे दलहन की सस्ती आपूर्ति करने और उत्पादकों को समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किए जा रहे बफर स्टॉक के लिए सभी उत्पादक राज्यों के किसानों से तुअर, उड़द और मूंग की सीधी खरीद करें।

मंत्रिमंडलीय सचिव पीके सिन्हा ने आज आवश्यक जिनको की कीमतों और उनकी उपलब्धता, विशेषकर दलहनों की, की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की और सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करें तथा त्योहारों के दौरान इन जिनको की सस्ते दर पर उपलब्धता को सुनिश्चित करें। एक सरकारी बयान में कहा गया है, 'सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी दलहन

उत्पादक राज्यों में किसानों से दलहनों की सीधी खरीद का विस्तार करें।'

नाफेड के अलावा लघु कृषक कृषि व्यवसाय परिसंघ (एसएफएसी) तथा भारतीय खाद्य निगम

(एफसीआई) भी दलहनों की खरीद का काम कर रहे हैं। इन एजेंसियों ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में मूंग की खरीद शुरू कर दी है और वे जल्द ही बाजार में आवक के आधार पर अपनी खरीद का विस्तार करेंगे। उन्हें 15 सितम्बर से उड़द की खरीद करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कुछ स्थानों पर मूंग की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नीचे जाने के कारण मूंग की खरीद शुरू की गई थी।

बयान में कहा गया, 'सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को त्योहारी सत्र के दौरान सस्ते दरों पर इन जिनको की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है।'

## नहीं हटेगी स्टॉक सीमा

नई दिल्ली। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश भर के खुदरा बाजारों में दलहन की कीमतों में गिरावट आई है लेकिन सरकार व्यापारियों पर लगाई गई स्टॉक की सीमा को नहीं हटाएगी क्योंकि वह देखना चाहती है कि गिरावट का रुख स्थायी है अथवा नहीं।

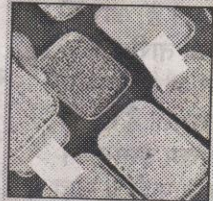
मंत्रों ने कहा कि सरकार दलहन की घरेलू कीमतें (एमएसपी) से घटने पर मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग करते हुए किसानों से दलहनों की खरीद करेगी। मंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि इस वर्ष दलहन का उत्पादन बढ़ेगा। वह मंत्रियों के एक समूह की बैठक में बोल रहे थे जिसकी अगुवाई वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे थे।

**किसानों को खाद सब्सिडी सीधे देने की प्रक्रिया तेज**

नई दिल्ली। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उर्वरक सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत लाने की व्यावहारिकता के अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जा चुका है और उससे तीन माह में रपट मांगी गई है। डीबीटी के तहत सब्सिडी

सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। कुमार ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने चालू खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए 14 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। रबी सत्र में यह प्रयोग और 14 जिलों में किया जाएगा। इनके नतीजों के आधार पर यह देशभर में लागू होगी। ■ भाषा

महंगाई की चिंता



त्योहारों पर जिनको की सस्ती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा

इन एजेंसियों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में मूंग की खरीद शुरू की

उड़द की खरीद 15 सितम्बर से और उसके बाद तुअर की खरीद शुरू होगी

5

राजश्री  
9-9-2016